शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 47 अंक-38 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 12-19 सितम्बर 2022 मूल्य पांच रूपए

प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में क्यों उभर रहे हैं विरोध के स्वर

पहले आनन्द फिर रामलाल ठाकुर और अब प्रतिभा सिंह के ब्यानों से उठी चर्चा

शिमला/शैल। पिछले कुछ अरसे से प्रदेश कांग्रेस के कुछ बड़े नेता भाजपा और जयराम सरकार पर हमलावर होने के बजाये अपने संगठन पर ही ज्यादा हमलावर होते नजर आ रहे हैं। यह सिलसिला बड़े नेता आनन्द शर्मा से शुरू होकर रामलाल ठाकुर से होते हुए प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रतिभा

सिंह तक पहुंच गया है।आनन्द शर्मा ने चुनाव कमेटी की अध्यक्षता से यह कहकर त्यागपत्र दे दिया कि उन्हें उचित मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इस आश्य का पत्र सीधे सोनिया गांधी को भेजा दिया। लेकिन आनन्द के त्यागपत्र पर संगठन में कोई बड़ी हलचल नहीं हुई क्योंकि वह बहुत पहले ही जी-23 समूह के बड़े नेता के रूप में चिन्हित हो चुके थे। आनन्द के बाद रामलाल ठाकुर ने पार्टी के उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। यह त्यागपत्र देते हुए जो सवाल उन्होंने अब सार्वजनिक रूप से संगठन पर उठाये हैं उन पर वह अब तक चुप क्यों थे। जब अपराधिक छवि के लोग संगठन में महत्वपूर्ण होते जा रहे थे तब वह खामोश क्यों थे। क्योंकि अब जब उन्हीं के उठाये हुये प्रश्न उन्हीं से पूछे जाएंगे तब क्या उत्तर देंगे? यह सवाल उठने के बाद भी वह किस नैतिकता से संगठन में बने हुए हैं इसका जवाब शायद वह न दे पायें। क्योंकि गलत समय पर यह सवाल उठाये गये हैं। जबकि इसी दौरान जब कार्यकारी अध्यक्ष पवन काजल और विधायक लखविंदर राणा पार्टी छोड़ कर गये थे तब यह सवाल पार्टी के भीतर उठाने का एक अच्छा अवसर था। इस समय सार्वजनिक रूप से यह सवाल उठाना संगठन को मजबूत करने की बजाये कमजोर करने का ज्यादा प्रयास माना जायेगा।

लेकिन अब जो साक्षातकार दी प्रिंट में प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का सामने आया है उससे प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में एक तरह से भूचाल की स्थिति खड़ी कर दी है। क्योंकि इस साक्षातकार के सामने आने के बाद प्रतिभा सिंह ने जो खण्डन जारी किया है उसके प्रत्युत्तर में दी प्रिंट ने पूरी स्क्रिप्ट का यूटयूब पर वीडियो जारी कर दिया है जिसे लाखों लोगों ने देख लिया है। इस साक्षातकार के सामने आने से यह सन्देह बन जाता है कि या तो प्रतिभा सिंह आज के राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य का सही में आकलन ही नहीं कर पायी है या फिर वह किसी राजनीतिक डर के साये में चल रही है। क्योंकि पिछले दिनों जब विक्रमादित्य सिंह ने सीबीआई को लेकर ट्वीट किया था उस समय यह सन्देश उभरा था कि आने वाले दिनों में हिमाचल में केंद्रीय जांच एजैन्सियों का दखल देखने को मिल सकता है। अब जब ऊना में रेत खनन माफिया के खिलाफ ईडी ने छापेमारी को अंजाम दिया है उससे यह आशंका का एकदम सही ठहरती है। क्योंकि ऊना में अवैध खनन का मामला शीर्ष अदालत तक पहुंचा हुआ है। इस पर अदालती जांच तक हो चुकी है। लेकिन उस समय ईडी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। संभव है कि अब चुनावी वक्त में इस छापेमारी की आंच कुछ राजनेताओं तक भी पहुंचे। ऐसे में राजनेताओं को इस तरह की स्थिति के लिये हर समय तैयार रहना होगा। लेकिन जिस तरह के ब्यान वरिष्ठ नेताओं के आने शुरू हो गये हैं उससे बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गये हैं।

इस सरकार के खिलाफ पूरे कार्यकाल में सदन के बाहर कोई बड़ी आक्रमकता देखने को नहीं मिली है। सरकार पर सवाल उठाने के बजाय कांग्रेस के नेता अपने अध्यक्ष बदलने पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते रहे हैं। सदन में तो चर्चा रही कि यह सरकार सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली सरकार के रूप में जानी जायेगी। लेकिन इस चर्चा को आम आदमी तक पहुंचाने के लिये कोई काम नहीं किया गया। आज चुनाव के वक्त तक जो संगठन सरकार के खिलाफ कोई आरोप पत्र न ला पाये उसकी नीयत के बारे में आम आदमी में सवाल उठने स्वाभाविक हैं। क्योंकि जब कांग्रेस ने आरोप पत्र बनाने के लिए कमेटी गठित की और आरोप पत्र जारी करने की तारीख तक घोषित कर दी थी तब मुख्यमंत्री ने भाजपा द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ सौंपे आरोप पत्र की जांच सीबीआई को सौंपने की बात की थी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद आज तक कांग्रेस का आरोप तक चर्चा से बाहर है। जबकि इस सरकार के खिलाफ तो पहले वर्ष से ही पत्र बम आने शुरू हो गये थे जयराम सरकार के आधे मंत्री परोक्ष अपरोक्ष में इन बमों के साये में हैं। सरकार का शीर्ष प्रशासन गंभीर सवालों के घेरे में चल रहा है। जिस सरकार में यह सारा कुछ रिकॉर्ड पर चल रहा हो उसका मुख्य विपक्षी दल इस तरह के अन्त: विरोधों का शिकार हो जाये तो निश्चित रूप से आम आदमी पर इस पर भ्रमित होगा ही।

क्या हाटी मुद्दे पर सरकार अध्यादेश लायेगी

शिमला/शैल। केन्द्र सरकार ने सिरमौर के गिरी पार के हाटीयों को जनजातीय दर्जा दिया जाना स्वीकार कर लिया है। प्रदेश सरकार ने इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि करार देते हुए बड़े स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया है। केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल के इस फैसले के बाद संसद में इस आश्य का संविधान संशोधन लाया जायेगा। संसद का सत्र अब वर्ष के अन्त में आयेगा जिसमें यह संशोधन पारित होगा। इस कारण अभी तुरन्त प्रभाव से इन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पायेगा। अभी जो भर्तियां बगैरा सरकार करेगी उसमें इस लाभ से यह लोग वंचित रह जायेंगे। ऐसे में यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि यदि प्रदेश सरकार सही में इस पर गंभीर है तो केन्द्र से इसमें अध्यादेश जारी कर इसे तुरन्त प्रभाव से लागू कर सकती है। अन्यथा यह आशंका बराबर बनी रहेगी कि यह मुद्दा भी अंत में कहीं एक जुमला बनकर ही न रह जाये। क्योंकि इस पर कुछ समुदायों में रोष भी फैल गया है। लोग विरोध में धरने प्रदर्शनों पर आ गये हैं। बल्कि यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय तक भी पहुंच गया है।

स्मरणीय है कि हाटी का मसला हर चुनाव से पहले मुखर होता रहा है। 1995 और 2006 में दो बार इस पर पूर्व में विचार हो चुका है। किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष को जन जातिय दर्जा देने के कुछ मानक तय हैं। लेकिन यह समुदाय इन मानकों पर पूरा नहीं उतरता रहा है। इसलिये राज्य सरकार के इस आश्य के प्रस्ताव भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा अधिकार होते रहे हैं। इसमें 14 फरवरी 2017 को आया पत्र महत्वपूर्ण है। इस परिदृश्य में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यदि 2017 में यह समुदाय जनजातिय मानकों को पूरा नहीं कर रहा था तो आज 2022 में यह कैसे संभव हो सकता है। 2017 के पत्र के परिदृश्य में सरकार के लिये यह स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव का प्रारूप सामने नहीं आ पाया है। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि सरकार अपनी गंभीरता और ईमानदारी दिखाने के लिए केन्द्र से अध्यादेश जारी करने का आग्रह करे। भारत सरकार का फरवरी 2017 का पत्र पाठकों के सामने रखा जा रहा है ताकि इस पर अपनी राय बना सकें।

भारत सरकार का पत्र

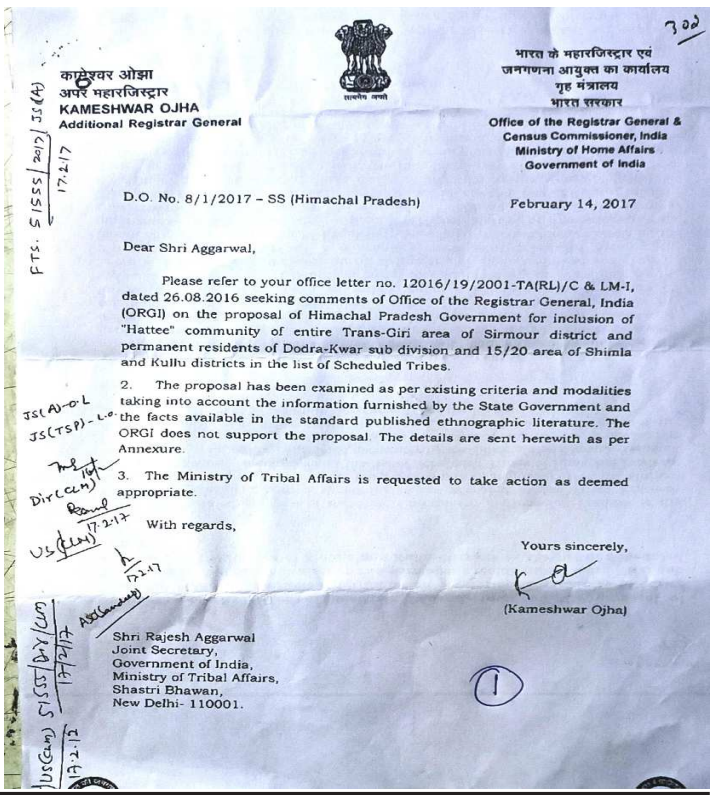

कामेश्वर ओझा
अपर महारजिस्ट्रार
KAMESHWAR OJHA
Additional Registrar General

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
Office of the Registrar General & Census Commissioner, India
Ministry of Home Affairs
Government of India

D.O. No. 8/1/2017 - SS (Himachal Pradesh) February 14, 2017

Dear Shri Aggarwal,

Please refer to your office letter no. 12016/19/2001-TA(RL)/C & LM-I, dated 26.08.2016 seeking comments of Office of the Registrar General, India (ORGI) on the proposal of Himachal Pradesh Government for inclusion of "Hattee" community of entire Trans-Giri area of Sirmour district and permanent residents of Dodra-Kwar sub division and 15/20 area of Shimla and Kullu districts in the list of Scheduled Tribes.

2. The proposal has been examined as per existing criteria and modalities taking into account the information furnished by the State Government and the facts available in the standard published ethnographic literature. The ORGI does not support the proposal. The details are sent herewith as per Annexure.

3. The Ministry of Tribal Affairs is requested to take action as deemed appropriate.

With regards,

Yours sincerely,

(Kameshwar Ojha)

Shri Rajesh Aggarwal
Joint Secretary,
Government of India,
Ministry of Tribal Affairs,
Shastri Bhawan,
New Delhi- 110001.

राज्यपाल ने सांगला में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर किन्नौर जिले के सांगला से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि

सभी के साझा प्रयासों से वर्ष 2023 तक प्रदेश से टीबी का उन्मूलन करने की दिशा में हम आगे बढ़ें ताकि हिमाचल प्रदेश टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त कर देश का पहला टीबी मुक्त राज्य बन सके। उन्होंने कहा कि इस अभियान को शुरू करने के लिए जनजातीय जिले किन्नौर को चुना गया है।

राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल के कारण टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां आई हैं, लेकिन सबके साझा प्रयासों से हम इस लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। उन्होंने कहा कि टीबी की जांच में सहयोग करना पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और अभियान को गति प्रदान कर टीबी मरीजों की सहायता की जा सकती है। उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कॉर्पोरेट क्षेत्र और बड़े व्यवसायी इस दिशा में योगदान देने के लिए आगे आए हैं और टीबी रोगियों के उपचार की जिम्मेवारी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य रेडक्रॉस भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

उन्होंने सभी से टीबी पीड़ित एक व्यक्ति को गोद लेकर उसे हर संभव सहायता प्रदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में टीबी के 12.30 लाख मामले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2021 में प्रति लाख जनसंख्या पर 191 मामले थे। राज्य में वर्ष 2021 में टीबी के कुल 14492 मामले थे, जिनमें से 2.6 प्रतिशत जनजातीय क्षेत्रों में, 74 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में और 23. 4 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में थे।

राज्यपाल ने कहा कि किन्नौर जिले में टीबी उन्मूलन की दिशा में जेएसडब्ल्यू हाईड्रो एनर्जी लिमिटेड सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने कम्पनी द्वारा 10 टीबी मरीजों को गोद लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने पूरे जिले को गोद लेने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे टीबी उन्मूलन की दिशा में सहायता मिलेगी।

राज्यपाल ने लाभार्थियों को जेएसडब्ल्यू एनर्जी बासपा प्लांट द्वारा प्रदान की गई पोषण किट भी वितरित की। उन्होंने इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य किट भी वितरित किए गए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबन्ध निदेशक गोपाल बेरी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने एनआई-क्षय 2.0 पोर्टल के कार्य और अपेक्षित परिणामों के बारे में भी जानकारी दी।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, उपमण्डलाधिकारी (नागरिक) शशांक गुप्ता, जेएसडब्ल्यू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के एसोसिएट वाईस प्रेजिडेंट और संयंत्र प्रमुख कौशिक मलिक, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने छितकुल गांव का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किन्नौर जिले के सीमावर्ती गांव छितकुल में गांववासियों

के साथ संवाद किया। राज्यपाल ने स्थानीय मंदिर में पूजा-अर्चना एवं परिक्रमा की। गांव की संस्कृति और परंपराओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यपाल स्थानीय निवासी मुकेश नेगी के घर गए। उन्होंने पारंपरिक तंदूर, रहन-सहन, खान-पान और रीति-रिवाजों के संबंध में करीब से जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय व्यंजनों का स्वाद भी लिया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि छितकुल की परंपराएं और रीति-रिवाज बहुत समृद्ध हैं, जिन्हें हर हाल में संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें यहां आने और पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मुश्किलों को करीब से समझने का मौका मिला है। उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पादों और परंपराओं को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर छितकुल गांव के प्रधान सुभाष, उप-प्रधान राजेश कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने हिन्दुस्तान-तिब्बत सीमा पर सैनिकों को राखी बांधी

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किन्नौर जिले के मस्तरांग छितकुल और नागेस्ती स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस की द्वितीय कोर की चौकियों का दौरा किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने गोवा के विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा भेजी गई राखियों को स्वयं सैनिकों की कलाईयों पर बांधा तथा बच्चों की ओर से स्नेह एवं प्रेषित

संदेश सैनिकों तक पहुंचाए। इस दौरान महिला सैनिकों ने भी राज्यपाल की कलाई पर राखियां बांधी। राज्यपाल ने नागेस्ती चौकी पर सेना के जवानों को भी राखियां बांधी।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि गोवा के बच्चों ने अपने नाम, अपने स्कूल तथा कक्षा के नाम के साथ ये राखियां भेजी हैं। उन्होंने बताया कि गोवा का एक संगठन हर साल बच्चों से राखी इकटठा करके सैनिकों को भेजता है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने तय किया कि वह खुद सैनिकों के बीच राखी लेकर आएंगे। राज्यपाल ने कहा कि पिछले साल उन्होंने लाहौल-स्पीति के सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर राखियां बांधी थीं। राज्यपाल ने कहा कि इस बार वह किन्नौर में आईटीबीपी की द्वितीय बटालियन के जवानों के बीच आकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं।

राज्यपाल ने कहा, जवान वर्ष भर हमारी रक्षा करते रहते हैं और इसलिए उनके लिए हर समय रक्षा बंधन है। उन्होंने कहा कि गोवा से जो राखी आई हैं, वह गोवावासियों का इन जवानों के प्रति स्नेह का प्रतीक हैं।

राज्यपाल कहा कि सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिक वास्तव में हमारी रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमाओं की रक्षा के लिए देश के हर कोने से सैनिक आते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर वे हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। जवानों का आभार व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने इन चौकियों के खूबसूरत परिसर की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि यह गोवा से भी ज्यादा सुन्दर हैं और वह यहां कुछ दिन रुकना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि सैनिक प्रकृति की भी रक्षा कर रहे हैं।

आईटीबीपी के डीआईजी प्रेम सिंह ने चौकियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने सैनिकों के साथ अल्पाहार लिया और उनके साथ कुछ समय भी व्यतीत किया।

राज्यपाल ने नीट-2022 के प्रदेश टॉपर को सम्मानित किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर से राजभवन में नीट-2022 में हिमाचल प्रदेश में

प्रथम स्थान पर रहने वाले आदित्य राज शर्मा को सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। आदित्य की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उनकी इस उपलब्धि से प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। वह प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। राज्यपाल ने आदित्य राज के अभिभावकों और शिक्षकों को भी बधाई देते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा और योगदान से आदित्य प्रथम स्थान अर्जित करने में सफल हो पाए हैं। इस अवसर पर एस्पायर एकेडमी के प्रबन्धक और आदित्य राज की माता उपस्थित थी।

एनडीआरएफ के तहत हिमाचल को केन्द्र से 200 करोड़ रुपये की अन्तरिम सहायता राशि जारी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एनडीआरएफ) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश को 200 करोड़ रुपये की अंतरिम सहायता राशि जारी करने पर केन्द्र सरकार और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई भारी क्षति को देखते हुए केन्द्र सरकार से एनडीआरएफ के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता तथा विशेष राहत प्रदान करने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए पहले राज्य आपदा राहत निधि (एसडीआरएफ) की 191.90 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त दिसम्बर माह के बजाए 29 अगस्त, 2022 को ही जारी कर दी, जिससे आपदा राहत कार्यो में तेजी लाई जा सकी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 16 सितम्बर, 2022 को केन्द्र की ओर से एनडीआरएफ के तहत 200 करोड़ रुपये की अंतरित सहायता राशि प्रदेश को अग्रिम रूप में जारी की गई है। इससे प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान से प्रभावित लोगों को समुचित राहत सहायता राशि व अन्य राहत एवं पुनर्निर्माण कार्यो में मदद मिल सकेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान मानसून में भारी वर्षा, भू-स्खलन और बादल फटने की घटनाओं में 29 जून, 2022 से 16 सितम्बर, 2022 तक जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई भारी क्षति का जायजा लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से अन्तर मन्त्रलय केन्द्रीय दल को भेजने का अनुरोध किया गया था। प्रदेश सरकार के अनुरोध पर अन्तर मन्त्रालय केन्द्रीय दल के 6 सदस्यों ने मानसून के दौरान ही प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का 28 अगस्त 2022 से 30 अगस्त, 2022 तक दौरा किया था।

सरकार के पोस्टर व बैनर फाड़ने वालों के विरूद्ध होगी कानूनी कारवाई

शिमला/शैल। प्रदेश के कुछ जिलों मे सरकार के पोस्टर व बैनर फाडने की घटनाएं हो रही है। हाल ही में ऐसी एक घटना जिला शिमला के रोहडू मे सामने आयी है जिस में एन.एस.यू.आई. के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के पोस्टर/बैनर फाडे गये हैं। इस घटना में संलिप्त आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा पुलिस द्वारा 03 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त जिला कांगड़ा, कुल्लू, सोलन व सिरमौर से भी इस प्रकार की घटनाओं की शिकायतें प्राप्त हुई है। इन सभी घटनाओं के बारे में सम्बन्धित थानों में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। इस सन्दर्भ में संजय कुन्डू, पुलिस महानिदशेक ने समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को इस तरह की वारदात में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध त्वरित कानूनी कारवाई करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश की सभी राजनैतिक पार्टीयों के कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे अपनी पार्टी का प्रचार शान्ति पूर्वक ढ़ंग से करे तथा सरकार के पोस्टर व बैनर फाड़ने की घटनाओं में शामिल न हो। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया गया तो उसके विरूद्ध कारवाई की जाएगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकःजे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

मुख्य सचिव ने की राष्ट्रीय राजमार्गों के कार्यों की समीक्षा

शिमला/शैल। मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव भरत खेड़ा ने प्रदेश में निर्माणाधीन एन.एच.ए.आई. की विभिन्न परियोजनाओं और लोक निर्माण विभाग-एनएच द्वारा किए जा रहे कार्यों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे एन.एच.ए. आई. के सदस्य मनोज कुमार भी बैठक में उपस्थित रहे।

प्रदेश में एन.एच.ए.आई. के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही फोरलेन हाईवे की पांच परियोजनाओं परवाणू-शिमला, शिमला-मटौर, मंडी-पठानकोट, पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ और कीरतपुर-मनाली के संबंध में बैठक में विस्तार से चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा, मुख्य सचिव ने भारी बारिश के कारण विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान, इनकी मरम्मत और रखरखाव के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की और एन.एच.ए.आई. तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए।

परवाणू-शिमला राजमार्ग पर भारी भूस्खलन पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने एनएचएआई अधिकारियों को पहाड़ियों के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने तथा इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एनएचएआई के सदस्य ने पहाड़ियों के संरक्षण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर अगले मॉनसून से पहले पूरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने बारिश के मौसम में राष्ट्रीय राजमार्गों को हुए नुकसान की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक धनराशि अतिशीघ्र जारी करने का भरोसा भी दिया। इस बैठक में विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने भी वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और मतदाता जागरूकता अभियानों पर दें विशेष बल:मुख्य निर्वाचन अधिकारी

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने राज्य में आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए हुई चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि युवा मतदाताओं के अनुपात में आशातीत

बढ़ौतरी के दृष्टिगत अब सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक मंचों के माध्यम से उन्हें मतदान प्रक्रिया में शामिल करने के लिए नवीन उपाय अपनाने की आवश्यकता है।

इस बैठक में प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) ने अपने जिलों में चुनाव की तैयारियों से संबंधित विस्तृत प्रस्तुति दी और कई मुद्दों पर चर्चा की गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दूर-दराज के मतदान केंद्रों का दौरा करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि राज्य के इन दूरस्थ क्षेत्रों में निर्वाचन प्रक्रिया का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग द्वारा पिछले विधानसभा चुनावों में 60 प्रतिशत से कम मतदान वाले 277 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शुरू किए गए मिशन 277 के अन्तर्गत कम मत प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने जिलों में मोबाइल प्रदर्शन वैन के माध्यम से ईवीएम पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और मतदाता जागरूकता अभियान चलाने को कहा। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए तृतीय लिंग के मतदाताओं और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) की पहचान करने और उन्हें शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं की पहचान करने की आवश्यकता है ताकि लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेने से कोई भी मतदाता पीछे न रहे।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फेक न्यूज और इसी तरह की सामग्री का पता लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिला निर्वाचन अधिकारियों को अपने जिलों में एक टीम गठित करनी चाहिए जो फेक और पेड न्यूज की निगरानी करें और उसकी रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि नियमित अंतराल पर विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।

जिला कानून प्रवर्तन एजेंसियों का यह कर्तव्य है कि ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सुनिश्चित करें और विभिन्न मतदान केंद्रों पर कर्मियों की पर्याप्त तैनाती की जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने व्यय की दृष्टि से संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों अथवा क्षेत्रों की निगरानी करने और स्थानीय मेलों और उत्सवों के दौरान स्वीप गतिविधियां संचालित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज की प्रभावी निगरानी नियमित आधार पर की जाए।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि चुनावी अपराधों पर सभी पुलिस कर्मियों, जांच अधिकारी (आईओ) के उचित प्रशिक्षण को सुनिश्चित कर प्रभावी प्रवर्तन तंत्र तत्काल लागू किया जाना चाहिए।

आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने वालों पर कसा शिकंजा, 3500 लीटर अवैध शराब नष्ट की

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी आयुक्त युनुस ने बताया कि विभाग की टीम ने पंजाब के साथ लगते कांगड़ा जिले के सीमान्त क्षेत्र छन्नी बेली एवं भदरोआ में दबिश देते हुए भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद की और इसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि विभाग ने इस कार्रवाई में हिमाचल होमगार्ड के जवानों की सहायता ली गई। विभाग के राजस्व जिला नूरपुर के प्रभारी टिक्कम ठाकुर द्वारा गठित इस टीम में नूरपुर, ज्वाली, इंदौरा वृत के सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे।

आयुक्त ने बताया कि इस टीम ने गांव भदरोआ के जंगलों में सर्च अभियान चलाया। इस टीम ने झाड़ियों में छिपाकर तैयार की जा रही कच्ची शराब एवं चार भठ्ठियां, प्लास्टिक के ड्रम, कैन इत्यादि और शराब बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली सामग्री अपने कब्जे में ली और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए मौके पर ही शराब नष्ट कर दी।

आयुक्त ने बताया कि विभाग को इस क्षेत्र में अवैध शराब के धंधे की सूचनाएं मिल रही थीं। सीमान्त क्षेत्र होने की वजह से यहां विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई करने में कुछ कठिनाइया भी आईं। इसके बावजूद विभाग ने इस क्षेत्र में कड़ी कारवाई करते हुए शराब की चार भठ्ठियां और 1850 लीटर कच्ची शराब कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद नष्ट कीं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सीमान्त क्षेत्रों में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक जिला स्तर पर टीम गठित करके अवैध शराब का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

जिला सिरमौर में भी विभागीय टीम ने पांवटा साहिब के साथ लगते खारा क्षेत्र में लगभग 1000 लीटर कच्ची शराब नष्ट की। इसके अलावा, राज्य के अन्य जिलों में भी अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 650 लीटर अवैध शराब कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई।

युनुस ने बताया कि समस्त जिला प्रभारी एवं क्षेत्र समाहर्ता प्रवर्तन प्रभारियों को अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कारवाई के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर किया रक्तदान शिविर का उद्घाटन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जोनल प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्तूबर, 2022 तक पूरे देश में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है।

अस्पताल मंडी में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि प्रदेश की जनता का यह सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री उनके प्रति विशेष स्नेह रखते हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने ईश्वर से नरेंद्र मोदी के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की, ताकि वह लंबे समय तक राष्ट्र को सशक्त नेतृत्व प्रदान करते रहें। मुख्यमंत्री ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। इस मौके पर विधायक जवाहर ठाकुर, प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री पवन राणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

स्वयं सहायता समूह संचालित करेंगे शहर के बुक कैफे: सुरेश भारद्वाज

शिमला। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बुक कैफे का संचालन आत्मनिर्भरता के एक नए मॉडल की शुरुआत है। इससे न केवल स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के लिए बाजार मिलेगा बल्कि शहरवासियों को पढ़ने-लिखने के लिए एक बेहतर स्थान भी उपलब्ध होगा।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाए-एनयूएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं शिमला के नवनिर्मित बुक कैफे संचालित करेंगी। शहरी विकास मंत्री चौड़ा मैदान स्थित बुक कैफे के माध्यम से 17 सितबंर, 2022 को स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालन के म डल का शुभारम्भ करेंगे।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि शिमला शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बुक कैफे का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा ''चौड़ा मैदान और छोटा शिमला में हाल ही में बुक कैफे का उद्घाटन भी किया गया है जबकि संजौली तथा न्यू शिमला में काम चल रहा है। इन बुक कैफे को चलाने के लिए विभिन्न म डलों का अध्ययन किया और यह निर्धारित किया गया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं इन बुक कैफे को चलाएंगी।''

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने शहरी क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को बाजार में स्थान देने का वादा किया था। महिलाएं न केवल अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने का काम करेंगी बल्कि बुक कैफे का प्रबंधन भी करेंगी।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि ''शिमला में 200 से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं। नगर निगम शिमला का एनयूएलएम. डिवीजन स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय करेगा और काम में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।''

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा महिलाओं को सशक्त करने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन पर बल दिया है। शहरी गरीबों का जीवन कठिन होता है क्योंकि उनके पास कृषि भूमि नहीं है और आजीविका के अवसर भी सीमित हैं। यह योजना कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के मेलों व प्रदर्शनियों में महिलाओं द्वारा मार्केटिंग का मुद्दा उठाया जाता था। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद की पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर पहले से ही काम किया जा रहा है और इनको एक बाजार उपलब्ध करवाने की दिशा में बुक कैफे एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। बुक कैफे न केवल इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बल्कि पढ़ने-लिखने वालों के लिए भी एक बेहतर मॉडल साबित होगा। चौड़ा मैदान का बुक कैफे विधानसभा के पास स्थापित पुस्तकालय के भार को कम करने में मददगार साबित होगा और बच्चों को पढ़ने-लिखने का स्थान भी मिलेगा।

सुरेश भारद्वाज ने कहा 'बुक कैफे को लेकर विभिन्न प्रकार के विकल्पों पर विचार किया गया, लेकिन इन स्थानों का व्यवसायीकरण न हो इसलिए महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा इनका प्रबंधन करने का निर्णय लिया गया है।'

शहरी विकास तथा सहकारिता मंत्री ने कहा कि वह इन स्वयं सहायता समूहों के लिए एक सहकारी मॉडल पर भी विचार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है। अब समय आ गया है कि इन समूहों को सम्बद्ध किया जाए और एक ऐसा समूह बनाया जाए जहां कम से कम सरकारी मदद की जरूरत हो और महिलाएं आत्मनिर्भरता के मॉडल की ओर बढ़ें।

हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बड़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके।
.....चाणक्य

सम्पादकीय

यह चुनावी घोषणाएं कहां ले जायेगी

अभी कुछ ही समय पहले जयराम सरकार ने 2600 करोड़ का कर्ज लिया है। यह कर्ज लेने के लिये सरकार को प्रतिभूतियों की नीलामी करनी पड़ी है। निश्चित है कि जब सरकार को कर्ज लेने के लिए प्रतिभूतियों की नीलामी करने पड़ जाये तो कर्ज लेने के अन्य सारे मार्ग समाप्त हो चुके होते हैं। प्रतिभूतियां सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा उठाये जाने वाले कर्ज की एवज में सरकार द्वारा दी जाती है। इस समय यदि सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्ज को मिलाकर देखें तो यह कर्ज एक लाख करोड़ से भी बढ़ जाता है। कर्ज की यह स्थिति इसलिये है क्योंकि एफ. आर.बी.एम. में संशोधन करके वित्तीय आकलनो के फेल हो जाने को अपराधिक जिम्मेदारी से बाहर निकाल दिया गया है। इस परिदृश्य में आज जब मुख्यमंत्री प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर करोड़ों की योजनाओं की घोषणाएं कर रहे हैं तो यह सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है कि क्या यह घोषणाएं जमीन पर उतर पायेगी या नहीं? इन घोषणाओं को पूरा करने के लिये कितना कर्ज लिया जायेगा और उसके लिए क्या-क्या गिरवी रखा जायेगा। यह सवाल इसलिये प्रसांगिक हो जाते हैं क्योंकि इन घोषणाओं को पूरा करने के लिये प्रदेश सरकार को अपने ही स्तर पर संसाधन जुटाने पड़ेंगे। केन्द्र की ओर से प्रदेश को अब तक क्या मिला है इसका सच प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और अन्त में मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमन्त्री के सामने रिज मैदान की सार्वजनिक सभा में रखें आंकड़ों से पता चल जाता है। प्रधानमंत्री ने मण्डी में यह आंकड़ा दो लाख करोड़ परोसा था। चम्बा में गृहमन्त्री ने एक लाख बीस हजार करोड़ तथा नड्डा 72000 करोड़ और रिज मैदान पर मुख्यमन्त्री ने 12000 करोड़ बताया था। सूचना और जनसंपर्क विभाग के प्रेस नोट में यह दर्ज है।

जबकि 31 मार्च 2020 को सदन के पटल पर रखी कैग रिपोर्ट के मुताबिक 2019 तक केन्द्रीय योजनाओं में प्रदेश को एक भी पैसा नहीं मिला है। कैग के मुताबिक ही सरकार 96 योजनाओं में कोई पैसा नहीं खर्च कर पायी है । बच्चों को स्कूल बर्दी तक नहीं दी जा सकी है। कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की किस्त तक नहीं दी जा सकी है क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं था। लेकिन 2019 में लोकसभा के चुनाव थे। 2019-20 के बजट दस्तावेज के मुताबिक इस वर्ष सरकार के अनुमानित खर्च और वास्तविक खर्चे में करीब 16,000 करोड़ का अन्तर आया है। कैग रिपोर्ट में यह दर्ज है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक हो जाता है कि जब केन्द्र ने कोई वितिय सहायता नही दी है तो इस बड़े हुये खर्च का प्रबन्ध कर्ज लेकर ही किया गया होगा। कैग रिपोर्ट पर आज तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय और मीडिया तक ने इस रिपोर्ट को शायद पढ़ने समझने का प्रयास नही किया है। इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुल बजट का 90% राजस्व व्यय हो चुका है। विकास कार्यो के लिए केवल 10% ही बचता है। वर्ष 2022-23 के 51,365 करोड़ का 10% ही जब विकास के लिये बचता है तो उसमें आज मुख्यमन्त्री द्वारा की जा रही घोषणाएं कैसे पूरी हो पायेगी? स्वभाविक है कि इसके लिये कर्ज लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जाता है।

आज मुख्यमन्त्री अपनी सरकार की सत्ता में वापसी के लिये हजारों करोड़ों दाव पर लगा रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों की घोषणाएं की जा रही है। अभी अगला चुनावी घोषणा पत्र तैयार हो रहा है। उसमें भी वायदे किये जायेंगे। विपक्ष भी इसी तर्ज पर घोषणा पत्रों से पहले ही गारटियों की प्रतिस्पर्धा में आ गया है। कन्द्र द्वारा प्रदेश को जो कुछ भी देना घोषित किया गया है वह अब तक सैद्धांतिक स्वीकृतियों से आगे नहीं बढ़ पाया है। प्रदेश के घोषित 69 राष्ट्रीय राजमार्ग इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर सरकार श्वेत पत्र जारी करने के लिये तैयार नहीं है और न ही विपक्ष इसकी गंभीरता से मांग कर रहा है। जयराम सरकार को विरासत में 46385 करोड़ का कर्ज मिला था लेकिन आज यह कर्जभार कहां पहुंच गया है इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। 1,76,000 करोड़ की जी.डी.पी. वाले प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्ज को मिलाकर यह आंकड़ा एक लाख करोड़ तक पहुंचना क्या चिन्ता का विषय नहीं होना चाहिये यह पाठकों के आकलन पर छोड़ता हूं।

उदयपुर घटना को इस्लाम से जोड़कर देखना ठीक नहीं

गौतम चौधरी

भारतीय गणतंत्र के पश्चिमी भाग में बसा बेहद शांत-सा प्रदेश विगत कुछ दिनों पहले एकाएक सुर्खियों में आ गया। दरअसल, राजस्थान में नूपुर शर्मा का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने को लेकर दो मुस्लिम युवा चरमपंथियों ने एक हिंदू दर्जी की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उन दोनों को गिरफ्तार तो कर लिया गया लेकिन इस घटना ने देश, दुनिया और खुद इस्लाम के समक्ष कई प्रश्न खड़ा कर दिया है। मंगलवार (28 जून, 2022) को हुई इस हत्या की भारत के लगभग सभी प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने निंदा की, जिनमें जमीयत उलेमा ए हिंद (जेयूएच), जमात ए इस्लाम हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आदि ने यह कह कर विरोध किया कि इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता और यह इस्लाम के खिलाफ है। के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने पैगंबर के अपमान के बहाने उदयपुर में नृशंस हत्या की घटना की निंदा की और इसे देश के कानून और इस्लाम धर्म के खिलाफ बताया। जेयूएच (एम) के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने इस घटना के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया, ''उदयपुर की घटना मानवता का अपमान है और इस्लाम को बदनाम करने का कार्य है। चाहे कोई भी हत्यारा हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कानून-व्यवस्था अपने हाथ में लें।''

पहले भी धार्मिक व्यक्तियों का अपमान करने और बदनाम करने के इस्लामी कानून पर अत्यधिक बहस हुई है और विद्वानों ने इसकी अलग-अलग व्याख्या की है। इस घटना के खिलाफ इस्लाम के लगभग सभी प्रमुख विद्वानों ने निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि इस्लाम में जो सहिष्णुता है उसके बारे में सब को जानकारी हो सके। पैगंबर का अपमान करने और उनके द्वारा क्षमा करने के अपने तरीके के बारे में सबसे बढिया उदाहरण पैगंबर मोहम्मद ने खुद प्रस्तुत किया है। इस्लाम में विश्वास करने वाले तमाम श्रद्धालु एक बूढ़ी औरत की कहानी के बारे में जरूर जानते हैं। वह बूढ़ी औरत पैगंबर पर कचरा फेंकती थी। दरअसल, पैगंबर जब उसके घर के पास से गुजरते थे तो वह उनके उपर कचरा फेंक देती थी। एक दिन नबी गुजरे लेकिन उन्होंने उस बूढ़ी औरत को अपने उपर कूड़ा फेंकते हुए नहीं देखा। खुशी व्यक्त करने के बजाय, पैगंबर उसके कचरा न फेंकने का कारण जानने गए। पैगंबर ने उससे मुलाकात की तो पता चला कि वह बूढ़ी औरत बीमार है। पैगंबर ने उसकी ओर रुख किया, उसे कोसने के बजाय उसके प्रति संवेदना व्यक्त की। पैगंबर के इस गुण और सहिष्णुता ने बूढ़ी औरत को इतना प्रभावित किया कि वह इस्लाम में दीक्षित हो गयी। एक अन्य घटना में जब सुहैल बिन अमर, एक कवि जिसने पैगंबर की निंदा करते हुए कविता की रचना की थी और जिसे बद्र की लड़ाई के बाद युद्धबंदी बना लिया गया था, पैगंबर ने उसे मारने का आदेश देने के बजाय अपने साथियों को उस पर दया दिखाने का आदेश दिया और उसे छोड़ दिया गया। यह साबित करने के लिए कई उदाहरण हैं कि पैगंबर ने किसी भी परिस्थिति में उन लोगों के खिलाफ हिंसा का सहारा नहीं लिया जो उनके प्रति पूरी तरह से अनादर का भाव रखते थे।

अगर इस्लाम में ईशनिंदक को मौत की सजा दी जाती, तो पैगंबर अपने सैकड़ों दुश्मनों को फांसी देने का आदेश देने वाले पहले व्यक्ति होते, जो उन्होंने नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ विचार रखने वालों में से अधिकतर इस्लाम के अनुयासी बन गए। यह मोहम्मद के सहिष्णु विचार का ही प्रतिफल था। भले ही मक्का में अधिकांश लोगों ने उनका विरोध किया, अनादर किया, तिरस्कार किया तथा उनकी निंदा की, या यहां तक कि उन्हें मारने की कोशिश की लेकिन पैगंबर ने क्षमा को अपना हथियार बनाया। उनके लिए दया और क्षमा लोगों को जीतने का सबसे बड़ा औजार था। पैगंबर मुहम्मद द्वारा क्षमा किये गए कुरेश नेता, जिसने पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ विभिन्न युद्धों का नेतृत्व किया इस्लाम की तारीख का सबसे बढ़िया उदाहरण है।

सच पूछिए तो ईशनिंदा का विचार इस्लाम में है ही नहीं। यह मध्ययुगीन मुस्लिम विद्वानों द्वारा ईसाई और यहूदी ग्रंथों से ली गयी है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि कुरान और पैगंबर की प्रामाणिक शिक्षाएं अज्ञानता, उद्देश्यपूर्ण उत्तेजना या शत्रुता के कार्यों के रूप में भगवान और उनके दूत के प्रति अवमानना व्यक्त करने की प्रथा को दर्शाती हैं। हालाँकि, इस्लामी शिक्षा के दो स्रोतों में से किसी ने भी कभी भी सैद्धांतिक असहमति, धार्मिक असहमति या अनादर के आधार पर दंडात्मक उपायों के उपयोग की वकालत नहीं की है। यह विशुद्ध रूप से इस्लाम के बाहर की चीज है और यह इस्लाम में तब से है जब इस्लाम पर साम्राज्यवादी प्रभाव का विस्तार हुआ। जो सवाल इन दिनों हर किसी को परेशान कर रहा है, वह है-भारतीय मुसलमानों के लिए अपमानजनक टिप्पणियों का जवाब देने का सही तरीका। देश के कानून के अनुसार किसी भी तरह के अनादर या निंदा के लिए कानून बने हैं। इसके आधार पर दंड भी दिए जा रहे हैं लेकिन यह देश सबके हित में ही अपना हित समझने वाला देश है। यहां कानून का राज है इसलिए किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेना कोई अधिकार नहीं है। किसी व्यक्ति की हत्या करना एक अपराध है और इससे कानून के सिद्धांतों के अनुसार निपटा जाना चाहिए। हिंसा के अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए और कानून उस संबंध में उदार नहीं होना चाहिए। इस्लाम शांति का धर्म है। पैगंबर मुहम्मद ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा शांति और भाईचारे के सन्देश देने में बिताया। हिंसा के माध्यम से इस्लाम को बदनाम करने का प्रयास करने वालों को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए ताकि अन्य लोग भी इससे सीख ले सकें।

शहरी स्वच्छता के लिए बड़ी संख्या में युवा हुए एकजुट

शहरों को कचरा मुक्त बनाने की दिशा में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के प्रयासों को नई गति मिली है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा शुरू किए गए एसबीएम-अर्बन 2.0 के तहत 'भारतीय स्वच्छता लीग' के पहले संस्करण में देशभर से 5 लाख युवा छात्र, स्वयंसेवक, युवा नेता और हस्तियां साथ आई। मिशन का उद्देश्य शहरों को स्वच्छ, हरा-भरा बनाने के साथ कचरा मुक्त करना है। 17 सितंबर 2022 से 2 अक्तूबर 2022 गांधी जयंती तक चलने वाले 'स्वच्छ अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में इस इंटर-सिटी लीग-आधारित स्वच्छता चैलेंज ने कचरा मुक्त समुद्र तटों, पहाड़ों और पर्यटन स्थलों के लिए रैली करने को 1800 से ज्यादा शहरों के युवाओं की ऊर्जा का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया।

शहर की टीमों ने विभिन्न रचनात्मक और अनूठी पहलों के जरिए स्वच्छता के प्रति अपने जुनून का प्रदर्शन किया। पंजाब में लुधियाना, महाराष्ट्र में पनवेल और पुणे, असम में पाठशाला, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सिटी टीमों ने युवाओं के साथ साइकिल रैली आयोजित कर स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों के महत्व को समझाया।

भोपाल, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ की युवा टीमों ने सबसे अलग अंदाज में कचरे को अलग-अलग रखने का संदेश दिया। करीब 5,000 युवा छात्रों की टीम बेमिसाल भोपाल ने मानव श्रृंखला बनाकर बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन के लिए छह बिन-सिस्टम को प्रदर्शित किया, जबकि टीम चंडीगढ़ चैलेंजर्स के 2,000 से अधिक छात्रों ने मानव श्रृंखला से चार डिब्बे प्रदर्शित किए।

समुद्र तट की सफाई के लिए भी युवाओं की टीम साथ आई। महाराष्ट्र के ग्रेटर मुंबई में करीब 4,000 स्वयंसेवकों ने 8 प्रमुख स्थानों के 49 समुद्र तटों से तीस टन कचरा साफ करने के लिए 50 किमी से अधिक दूरी तय की। पुरी और केरल की टीमों ने स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त समुद्र तटों का संदेश देने के लिए सैंड आर्ट (रेत कला) बनाया। जबकि टीम मंगलुरु स्वच्छता सोल्जर्स ने 11 अलग-अलग समुद्र तटों को साफ करने के लिए 5,000 युवाओं को तैनात किया। रामेश्वरम, तमिलनाडु के युवाओं और पोर्ट ब्लेयर की टीम प्रिस्टिन पोर्ट ब्लेयर ने भी भारतीय स्वच्छता लीग के पहले संस्करण में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।

लाखों युवाओं ने स्वच्छ और कचरा मुद्र पहाड़ों पर भी जोर दिया। जम्मू और कश्मीर के कई शहरों जैसे गांदरबल, पहलगाम, अनंतनाग और बिजबेहरा में हजारों युवाओं ने स्वच्छता को लेकर जागरुकता लाने के लिए रैली की। पूर्वोत्तर राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, असम, सिक्किम और नगालैंड की युवा शक्ति ने भी भारतीय स्वच्छता लीग में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

देशभर की टीमों ने बड़े पैमाने पर कचरा बीनने और सफाई का अभियान चलाया। अपने शहर की टीमों का सहयोग करने के लिए लाखों युवा साथ आए। झारखंड की टीम जमशेदपुर जगुआर, ओडिशा की टीम पारादीप टाइटन्स, टीम कोयंबटूर और रामेश्वरम तमिलनाडु, टीम सूर्यपेट तेलंगाना और टीम स्वच्छ विशाखा वारियर्स आंध्र प्रदेश ने आईएसएल में विशेष योगदान दिया।

युवाओं की अगुआई वाली इस प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ टीमों का चयन एक स्वतंत्र प्रक्रिया द्वारा होगा, जिसमें राष्ट्रीय ख्याति के जूरी सदस्य शामिल होंगे। भागीदारी के स्तर, गतिविधि की विशिष्टता और स्वच्छता पहल के प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि मिशन में और ज्यादा संख्या में युवा जुड़ेंगे। इसकी मदद से स्वच्छता अभियान के प्रभाव को देखते हुए स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन के लिए जमीनी कार्रवाई पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

बाबासाहेब के सपनों को साकार करते नरेन्द्र मोदी-राम नाथ कोविन्द

शिमला। भारतवर्ष अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है। यह आजादी का अमृत काल है। यह हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद करने का भी समय है जिन्होंने हमारे समाज के सबसे कमजोर तबकों और गरीब वर्गो की आकांक्षाओं और सपनों को पंख दिये। हालांकि आजादी के बाद से सभी सरकारों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है और समाज के सभी वर्गो के उत्थान के लिए काम किया है लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने व्यवहारिक रूप से बाबासाहेब अंबेडकर के अधूरे सपनों को साकार किया है।

आज प्रधानमत्रि नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन भी है जिनके साथ मेरा बहुत लंबा और यादगार जुड़ाव रहा है। मैंने उन्हें एक कार्यकर्ता के रूप में, कुशल संगठनकर्ता के रूप में, एक मुख्यमंत्री के रूप में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करते देखा है। प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने के पश्चात् संसद की सीढ़ियों को नमन करते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार देश के गाँव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, युवा एवं महिलाओं के कल्याण के प्रति समर्पित साकार होगी और विगत 8 वर्षो में प्रधानमंत्री ने निःसंदेह उसे चरितार्थ कर दिखाया है। वे समतामूलक समाज के विकास के लिए अहर्निश प्रयासरत रहे हैं। उनकी हर योजना में समाज के दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला एवं देश के अन्य कमजोर वर्गो के उत्थान की भावना दृष्टिगोचर होती है।

एक कुशल संगठनकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी बाबासाहेब के बताये रास्ते पर ही आगे बढ़े हैं। उन्होंने देश और दुनिया को बाबासाहेब के जीवन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण स्थलों को 'पंचतीर्थ' के रूप में विकसित कर उसे संजोने का उपहार दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बाबासाहेब के जन्मदिन 14 अप्रैल को समरसता दिवस और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय उनकी ओर से बाबासाहेब को दी गई भावांजलि है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर ही पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाबासाहेब की 125वीं जन्मजयंती मनाई थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दो महत्वपूर्ण कार्य जो वास्तव में बाबासाहेब अंबेडकर के सपनों को साकार करते हैं, वे हैं अनुच्छेद 370 का उन्मूलन और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु अनेक लोककल्याणकारी नीतियों और योजनाओं को धरातल पर प्रस्तुत करना। बाबा साहेब की कड़ी आपत्तियों के बावजूद, अनुच्छेद 370 हमारे संविधान का हिस्सा बन गया जिसके हटने की कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। यह प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ प्रतिबद्धता और इच्छाशक्ति थी, जिसके बल पर अनुच्छेद 370 निरस्त हुआ और जम्मू-कश्मीर सही मायनों में भारत का अभिन्न अंग बना। बाबा साहेब ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने पर जोर दिया था। यह नरेन्द्र मोदी हैं जो 'आत्मनिर्भर भारत' के वाहक बने हैं। इसके लिए मोदी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं।

राष्ट्रपति के रूप में जब भी मैं सामाजिक मुद्दों और शासन व्यवस्था पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा करता था तो मैंने हमेशा उनमें एकदम जड़ तक फैले भ्रष्टाचार को लेकर गहरी चिंता दिखी क्योंकि वे मानते हैं कि भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा पीड़ित गरीब लोग ही होते हैं। पिछले आठ वर्षो में नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है और वे यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की सभी जनोपयोगी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। आज सभी पात्र लाभार्थियों के एकाउंट में सभी सरकारी योजनाओं का लाभ हस्तांतरित किया जाता है। इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगा है।

वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति द्वारा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जबरन नियंत्रण को लेकर भी नरेन्द्र मोदी काफी चिंतित रहते हैं क्योंकि यह किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। यह सच्चाई है कि परिवारवाद की राजनीति सच्चे और मेहनती राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन कर रही है। नरेन्द्र मोदी ने हमेशा योग्यता के आधार पर ही कार्यकर्ताओं एवं नेताओं को बढ़ावा दिया है। परिवारवाद के बजाय योग्यता पर आधारित राजनीति निस्संदेह हमारे लोकतंत्र को और अधिक जीवंत और मजबूत बनाएगी।

नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'पद्म पुरस्कारों' का गौरव पुन: हासिल हुआ है। पद्म पुरस्कारों ने 'आम नागरिकों' के साथ अपना सहज संबंध पुन: स्थापित किया है। इन पुरस्कारों को लेकर पहले यह धारणा बन सी गई थी कि ये उन्हीं को मिलते हैं जिनकी पहुंच बड़ी होती है, पर नरेन्द्र मोदी सरकार में पद्म पुरस्कार आम नागरिकों के करीब लगने लगे हैं। यह बदलाव नई परम्परा का प्रतीक है और इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत किया जाना चाहिए जिसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की जनोन्मुखी सोच को जाता है।

मैं यहाँ आकांक्षी जिलों के विकास और आदर्श ग्राम योजना का भी जिक्र करना चाहूंगा। इन दोनों योजनाओं ने पिछड़े क्षेत्रों में विकास की नई कहानी लिखी है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, एकलव्य मॉडल स्कूल और आदिवासी गांवों के विकास की योजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में विकास को एक नया आयाम दिया गया है। नई शिक्षा नीति से गरीब से गरीब बच्चों को अपनी भाषा में उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय और जनजातीय संग्रहालयों का निर्माण भी एक अत्यंत सराहनीय कदम है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने कोविड के दौरान देश के सबसे कमजोर तबकों को बड़ा संबल प्रदान किया है। उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन-धन योजना, आयुष्मान भारत योजना, मिशन इंद्रधनुष, आवास योजना, किसान सम्मान निधि, स्टार्ट-अप, कौशल विकास आदि योजनाओं का सबसे अधिक लाभ देश के गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग को ही मिला है। ये सभी योजनायें गरीबों के बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संवेदनशीलता को दर्शाती है।

मैंने बहुत करीब से इस बात का अनुभव किया है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने घातक कोविड वायरस के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व और प्रोत्साहन के बल पर हमारे वैज्ञानिक 9 महीने से भी कम समय में एक नहीं बल्कि दो-दो 'मेड इन इंडिया' टीके विकसित करने में सफल हुए, जिसने न केवल हमें सुरक्षा कवच दिया बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में मानवता को बचाने का एक अवसर भी दिया। जब कोविड ने विकसित देशों को भी पंगु बना दिया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत और विस्तारित किया। साथ ही, देश के अर्थचक्र को भी अवरुद्ध नहीं होने दिया।

देश के विकास के लिए विगत 8 वर्ष कई मायनों में उल्लेखनीय और ऐतिहासिक रहे हैं। नरेन्द्र मोदी कई कालजयी व्यक्तित्वों से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन उनकी शासन पद्धति पर बाबासाहेब की अमिट छाप हर जगह दिखती है। मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी के रूप में इसलिए देखता हूं कि उन्होंने बाबा साहेब के पदचिह्नों पर चलते हुए 'राष्ट्र प्रथम' को अपना आदर्श वाक्य बनाया है, 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' को अपना मंत्र बनाया है और सुशासन, सामाजिक समरसता एवं अनुशासन को सरकार की पहचान बनाया है।

राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र में 16.51 लाख घरों को नि:शुल्क उपलब्ध करवा रही है पेयजल

पानीयं परमं लोके जीवानां जीवनं समृतम्।

इस सूक्त में जल की महत्ता को रेखांकित किया गया है। इसी से अभिप्रेरित जल जीवन मिशन के माध्यम से राज्य सरकार हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों से लेकर तलहटियों में बसे छोटे से छोटे गांव के हर घर तक पेयजल पहुंचाने के चुनौतीपूर्ण कार्य को बखूबी अंजाम दे रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2019 को देश के समक्ष नल से हर घर को शुद्ध जल उपलब्ध करवाने का संकल्प रखा था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रारम्भ किए गए जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाया जा रहा है। महिलाओं व बच्चियों को मीलों दूर स्थित प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाने की कड़ी मेहनत से छुटकारा दिलाना भी इस मिशन का उद्देश्य है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक घर में नल से जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में जहां प्रदेश तेजी से आगे बढ़ा है वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 96 प्रतिशत घरों में मुफ्त पेयजल प्रदान करने की पहल भी की है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 15 अप्रैल, 2022 को हिमाचल दिवस के मौके पर चंबा के चौगान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नि:शुल्क पेयजल (पानी) उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी। इससे ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 70 लाख आबादी प्रतिमाह लाभान्वित हो रही है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 17,27,518 घर हैं, जिनमें से राज्य सरकार द्वारा अब तक लगभग 16.51 लाख घरों को पेयजल कनेक्शन प्रदान कर नि:शुल्क पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

प्रदेश में जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन का सुखद परिणाम यह रहा कि चार जिलों किन्नौर, चम्बा, लाहौल-स्पीति और जिला ऊना में शत-प्रतिशत घरों में राज्य सरकार द्वारा नल कनेक्शन प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क पेयजल प्रदान किया जा रहा है तथा अन्य जिलों में भी 90 प्रतिशत से अधिक घरों तक नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान जल शक्ति विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में अब तक 46,853 घरों में नल कनेक्शन लगाए गए हैं।

शिमला जिला में ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कुल 1,73,123 में से 1,64,806 घरों, कुल्लू जिला में कुल 1,14,481 में से 1,06,634 घरों, कांगड़ा जिला में कुल 4,13,171 में से 3,89,167 घरों, सिरमौर जिला में कुल 1,21,248 में से 1,13,849 घरों, मंडी जिला में कुल 3,11,575 में से 2,93,148 घरों, हमीरपुर जिला में कुल 1,12,172 में से 1,06,488 घरों, सोलन जिला में कुल 1,13,821 में से 1,10,341 घरों, बिलासपुर जिला में कुल 1,00,179 में से 99,333 घरों में तथा किन्नौर जिला में सभी 22,763 घरों, चम्बा जिला में सभी 1,21,752 घरों, लाहौल-स्पीति जिला में सभी 7,284 घरों और ऊना जिला में सभी 1,15,949 घरों में अब तक नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं।

प्रदेश को वर्ष 2019 से अब तक लगभग 4567 करोड़ रुपये की राशि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत केंद्र से प्राप्त हुई है। नल कार्यशीलता व जल गुणवत्ता में हिमाचल को देश में सबसे आगे आंका गया है और सात राज्यों में अव्वल रहने पर 1028.43 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी केंद्र सरकार से प्रदेश को मिली है।

राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पानी का कनेक्शन लगवाने की प्रक्रिया और सरल की है तथा कोई भी व्यक्ति साधारण कागज पर अपना आवेदन पत्र देकर व उसके साथ आधार कार्ड की प्रतिलिपि लगा कर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का कनेक्शन लगवा सकता है। नल कनेक्शन के लिए पाईपें भी राज्य सरकार के जल शक्ति विभाग की ओर से नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं।

जल शक्ति विभाग ने दिसम्बर, 2022 तक प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों में नि:शुल्क जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके दृष्टिगत विभाग ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर को नि:शुल्क हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है।

ग्रामीण पृष्ठभूमि से सम्बंधित प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकताओं को भली-भान्ति समझते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को नि:शुल्क पेयजल प्रदान करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। सदानीरा नदियों के उद्गम स्थल हिमाचल में जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से शुद्ध जल उपलब्ध करवाने में उनके यह प्रयास अब रंग ला रहे हैं।

अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए हाटी समुदाय ने किया मुख्यमंत्री का अभिनंदन

शिमला/शैल। गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिये हाटी समिति द्वारा शिमला के पीटरहॉफ

में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के सम्मान में आभार समारोह आयोजित किया गया। समारोह में हाटी समुदाय के हजारों लोगों ने मुख्यमंत्री का अभिनन्दन किया।

जय राम ठाकुर ने हाटी समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि लम्बे समय तक साथ चलकर और संघर्ष से यह मंजिल हासिल की गई है। इतिहास में यह दिन स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अनेक बार यह मामला केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सिरमौर जिले के ट्रान्सगिरी क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जाति की आबादी यानी 91445 व्यक्तियों की भावनाओं को भी ध्यान में रखा है और उनके हितों की भी रक्षा की है। ट्रान्सगिरी क्षेत्र की कुल 251657 आबादी में से 160021 लोग अनुसूचित जनजाति के दर्जे से लाभान्वित होंगे।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और केन्द्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सभी को साथ लेकर प्रगति के पथ पर निरन्तर आगे बढ़ रही हैं तथा राज्य में हर वर्ग और हर क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से भावी पीढ़ियां भी खुशहाली के मार्ग पर अग्रसर होगी।

सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और केन्द्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा केन्द्रीय हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा सफल प्रयासों से ही सम्भव हो पाया है।

ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के प्रयासों से ही प्राप्त हुआ है।

विधायक रीना कश्यप ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने सिरमौर का भविष्य उज्ज्वल बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष बलदेव तोमर ने इस अवसर पर कहा कि इस ऐतिहासिक लड़ाई की जीत के लिए सिरमौर जिला की आने वाली पीढ़ियां सदैव मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को याद रखेंगी।

केन्द्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉ. अमिचंद कमल ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया और उसके उत्साहजनक परिणाम सामने आएं।

हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने पर सिरमौर के लोगों को बधाई:प्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति दर्जा घोषित करने पर सिरमौर के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सिरमौर जिला के लोग अपनी इस मांग को लेकर लम्बे समय से संघर्षरत थे और उनका यह संघर्ष सफल हुआ है,इसके लिये सिरमौर के लोग बधाई के पात्र है।

प्रतिभा सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान प्रदेश में हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने की मांग केंद्र से की थी,ओर उन्हें खुशी है कि आज स्व वीरभद्र सिंह की हाटी को जनजाति दर्जे की मांग फलीभूत हुई है।

प्रतिभा सिंह ने सरकार से इस फैंसले को तुरंत लागू करने को कहा है। हालांकि उन्होंने इस फैंसले को प्रदेश विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत लिये गया निर्णय करार देते हुए कहा है कि अब देखना यह होगा कि सरकार इस फैंसले को कब लागू करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने है, ऐसे में केंद्र सरकार ने प्रदेश की भाजपा सरकार को राजनैतिक लाभ देने के लिये संम्भता अब यह निर्णय लिया है। उन्होंने शंका जताई है कि कही यह निर्णय चुनावी जुमला ही साबित होकर न रह जाये, क्योंकि इन चुनावों में प्रदेश मे भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ेगा।

किन्नौर में पर्यटन गतिविधियों की अपार संभावनाएं: राज्यपाल

शिमला/शैल। किन्नौर जिले के सांगला में अम्बेडकर भवन में जिला प्रशासन और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि किन्नौर को पर्यटन की दृष्टि से और विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यहां पर्यटन योजना के तहत कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किन्नौर में ईको टूरिज्म के तहत यहां अगर व्यापक स्तर पर ठहरने की व्यवस्था होती है तो बाहर से आने वाला पर्यटक यहां रूकेगा जिसका स्थानीय स्तर पर काफी लाभ होगा और लोगों की आर्थिकी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

उन्होंने जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है और वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक उत्पादों की मांग है। उन्होंने कहा कि किन्नौर का सेब विश्व में प्रसिद्ध है और गोवा में भी किन्नौर के सेब की बहुत अधिक मांग है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि से जोड़ने पर यहां का सेब और अधिक ऊंचाइयां हासिल करेगा और लोगों को रसायनमुक्त उत्पाद मिलेगा। उन्होंने प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यो की प्रशंसा की।

उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का आहवान किया। इस अवसर पर उन्होंने 10 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस कनैक्शन वितरित किए।

इससे पूर्व, किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने प्रशासन के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं से राज्यपाल को अवगत करवाया।

इस अवसर पर उपस्थित पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि पंचायतों में उन्हें सरकारी योजनाओं का व्यापक लाभ मिल रहा है। उन्होंने राज्यपाल से करच्छम से निथल-थाच तक जा रहे मार्ग को स्तरोन्नत करने के लिए सड़क का मामला उचित स्तर पर उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह मार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने सांगला में पर्यटन अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण संस्थान आरम्भ करने का आग्रह किया ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि इस संस्थान को आरम्भ करने के लिए उनके पास जमीन भी उपलब्ध है।

पुलिस अधीक्षक विवेक चहल, जिला प्रशासन के अधिकारी, विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बागवानी में नई क्रांति ला रही है बागवानी विकास परियोजना: अमिताभ अवस्थी

शिमला/शैल। किसानों, बागवानों और कृषि उद्यमियों के सशक्तिकरण तथा उन्हें बैंकिंग योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से होटल हॉलीडे होम में एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना (एचपीएचडीपी) के तहत आयोजित इस सम्मेलन में बागवानी विभाग, एचपीएमसी, मार्केटिंग बोर्ड और बैंक

अधिकारियों के अलावा एचपीएचडीपी के अंतर्गत गठित क्लस्टरों तथा अन्य कृषक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया।

सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित करते हुए बागवानी और जलशक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि 1066 करोड़ रुपये की बागवानी विकास परियोजना हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक नई क्रांति का सूत्रपात कर रही है। इस परियोजना के तहत शीतोष्ण फलों विशेषकर सेब और गुठलीदार फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अमिताभ अवस्थी ने बताया कि इस परियोजना में बीज से लेकर बाजार यानि पौधारोपण से लेकर पौधों की देखभाल, सिंचाई, स्टोरेज, मूल्यवर्द्धन, प्रसंस्करण और विपणन सहित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। बागवानी क्षेत्र की इस पूरी श्रृंखला में बागवानों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है।

बागवानी सचिव ने बताया कि इस परियोजना के तहत सेब के 30 लाख पौधे आयात किए गए हैं। एक निर्धारित अवधि तक विभिन्न केंद्रों पर रखने के बाद इन्हें रियायतों दरों पर बागवानों को वितरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक लगभग 20 लाख पौधे वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन पौधों से हिमाचल में सेब का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ेगा तथा इनकी गुणवत्ता भी अच्छी होगी। अमिताभ अवस्थी ने बताया कि एचपीएचडीपी से छूटे प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए भी सरकार ने एचपीशिवा परियोजना आरंभ की है। इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश के 7 जिलों में लिची, अमरूद और नींबू प्रजाति के फलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस परियोजना के भी बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। बागवानी सचिव ने प्रदेश के किसानों-बागवानों से इन परियोजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। एक दिवसीय सम्मेलन के आयोजन की सराहना करते हुए अमिताभ अवस्थी ने कहा कि इससे किसान-बागवान विभिन्न बैंकिंग योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

एचपीएचडीपी के परियोजना निदेशक सुदेश मोक्टा ने परियोजना के तहत आयोजित विभिन्न गतिविधियों तथा उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एचपीएचडीपी के तहत अभी तक 272 क्लस्टरों में लगभग 6000 हैक्टेयर भूमि पर सेब का घना पौधारोपण किया जा चुका है, जबकि 8800 हैक्टेयर पुराने बागीचों में भी नए पौधे रोपे जा चुके हैं। सिंचाई योजनाओं के बेहतर संचालन के लिए 261 वाटर यूजर्स एसोसिएशनों का गठन किया गया है तथा 30 फार्मर प्रोडयूसर कंपनियां भी बनाई जा चुकी हैं। परियोजना के तहत 9 मंडियों का आधुनिकीकरण किया गया है तथा आपूर्ति श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण तथा कोल्ड चेन से संबंधित आधुनिक सुविधाओं के लिए 15 इकाईयों हेतु वित्त पोषण की प्रक्रिया पूर्ण की गई है। सुदेश मोक्टा ने बताया कि परियोजना के 60 से 65 प्रतिशत तक कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

सम्मेलन के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक आरएस अमर, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. एसकेके मिश्रा, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारी एसएस नेगी और अन्य बैंक अधिकारियों तथा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी जीसी राजू ने विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

परियोजना की टीम लीडर डॉ. प्रबल चौहान ने विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया। जबकि, संदीप कुमार ने कार्यक्रम का संचालन किया।

इस अवसर पर बागवानी विभाग के निदेशक डॉ. आरके प्रथी, एचपीएमसी के महाप्रबंधक हितेश आजाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

भवन बनाने के लिए पंजीकृत निजी पेशेवर दे सकेंगे अनुमति:सुरेश भारद्वाज

शिमला/शैल। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यहां बताया कि प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों और हिमुडा के 500 वर्गमीटर तक के आवासीय प्लाटों में रिहायशी भवन बनाने की अनुमति अब पंजीकृत निजी पेशेवर भी दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश में आम लोगों को मकान बनाते समय नगर एवं ग्राम योजना विभाग (टी.सी.पी) के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इससे पंजीकृत निजी पेशेवर, स्थल निरीक्षण व निरीक्षण रिपोर्ट करने के बाद केवल 30 दिनों के भीतर हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 के तहत विकास अनुमति की अनुज्ञा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि निजी पेशेवर जिन्हें एक वर्ष से ज्यादा का अनुभव है केवल वही इस आदेश के तहत भवन बनाने की अनुमति प्रदान कर पाएंगे।

उन्होंने कहा कि इस आदेश के तहत सभी अनुमतियां पंजीकृत निजी पेशेवरों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी। इस कार्य के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत निजी पेशेवरों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त विभाग यह भी सुनिश्चित करेगा कि निजी पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई अनुमतियों में कोई अनियमितताएं व विसंगतियां न हो। इसके लिए कम से कम 10 प्रतिशत अनुमतियों का सक्षम अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा।

शहरी विकास मंत्री ने बताया कि इस आदेश के लागू होने के उपरान्त नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, स्थानीय निकायों, व साडा द्वारा ही बिजली व पानी के कनैक्शनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, भू-उपयोग परिवर्तन व भू-विभाजन की अनुमति दी जाएगी।

जलशक्ति मंत्रालय से 2167.72 करोड़ की हिमाचल में पांच बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की मांग:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल व युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग सिंह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से मिलकर हिमाचल प्रदेश में लगभग 2167.72 करोड़ रुपये की लागत से पांच बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की माँग की है।

अनुराग ठाकुर ने कहा प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश को सदैव अपना दूसरा घर माना है और हिमाचल की आवश्यकतानुसार हर ज़रूरी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में दैवीय आपदा के चलते हर बरसातों में बाढ़ आम बात है जिसके चलते हर साल काफी जान-माल का नुक़सान होता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी से मिलकर उनके समक्ष इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए हिमाचल में 2167.72 करोड़ की लागत से हिमाचल में पांच बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं की मांग प्रमुखता की है। केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की जयराम सरकार हिमाचल के चहुंमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है।

अनुराग ठाकुर ने कहा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हिमाचल में पांच में से तीन बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं की मांग हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में की है। हिमाचल में बाढ़ सुरक्षा परियोजनाएं में से प्रमुखता से फिना सिंह बहुउद्देशीय परियोजना जोकि 643.68 करोड़ रुपये की लागत से होगी वह 1.88 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। मण्डी जिले में ब्यास जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत सुकेती खड्ड नदी के साथ-साथ उसकी सहायक नदियों पर बाढ़ सुरक्षा उपाय और नहर निर्माण परियोजना शुरू की जानी है। इस परियोजना से 41 हजार से अधिक लोगों को लाभ होगा और 881 हेक्टेयर क्षेत्र संरक्षित होगा। इस परियोजना पर कुल 485.23 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी प्रकार, ऊना जिले की अम्ब तहसील में स्वां नदी और उसकी सहायक नदियों के लिए बाढ़ सुरक्षा उपाय प्रदान करने की परियोजना से 14 हजार से अधिक लोगों को लाभ होगा और 510 हेक्टेयर क्षेत्र संरक्षित होगा। इस पर परियोजनाओं पर 339.25 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। तीसरी परियोजना बाढ़ सुरक्षा और विभिन्न खड्डों के लिए कटाव रोकने के उपाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किए जाएंगे तथा इससे 23 हजार से अधिक लोगों को लाभ होगा और 811 हेक्टेयर क्षेत्र संरक्षित होगा। इस परियोजना पर 504.07 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

सीर खड्ड पर बाढ़ सुरक्षा कार्यो पर 195.49 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इसे बिलासपुर जिले के घुमारवीं तहसील के तलवारा गांव से बालघाट तक किया जाएगा। इस परियोजना से 14 हजार से अधिक लोगों को लाभ होगा और 179 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र संरक्षित होगा।

अनुराग ठाकुर ने कहा पूर्व में

जनमानस की मांग और क्षेत्र के विकास को देखते हुए साल 2000 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्र में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से स्वां नदी के तटीयकरण के लिए के लिए 106 करोड़ रुपए आवंटित करा कर इस परियोजना की शुरूआत करी, जिसके अंतर्गत मुख्यत:स्वां नदी के साथ 77 सहायक नदियों के तटीयकरण करना इस परियोजना का उद्देश्य था, जिसमें केंद्र और राज्य की क्रमश: 90% और 10% खर्च की हिस्सेदारी थी। स्वां तटीयकरण से अब तक करीब 12000 हेक्टेयर भूमि ज़िला ऊना में कृषि योग्य बनाई गई है, जिससे किसानों को राहत मिली है । अब यह मौजूदा मांग राज्य में नदी की बाढ़ से जान-माल की क्षति को कम करने में एक लंबा सफर तय करेगी। मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह उस दिशा में उठाए गए कई कदमों में से एक है।

छह मुख्य 'थीम' बदल देंगे राज्य में पर्यटन परिदृश्य

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने धर्मशाला में आयोजित किए जा रहे विभिन्न प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक गतिविधियां, सप्ताहांत, ग्रामीण

और जनजातीय पर्यटन सहित छह मुख्य विषयों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और अब सरकार ने अनछुए स्थलों को तलाशने के लिए नई पहल की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की 'नई राहें, नई मंजिलें' योजना राज्य के कई सुंदर एवं अनछुए स्थलों को पर्यटन मानचित्र पर लाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जंजैहली में ईको टूरिज्म, चांशल घाटी में स्कीइंग और बीड बिलिंग क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग दुनिया भर के प्रकृति एवं साहसिक खेल प्रेमियों को आकर्षित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जलविद्युत परियोजनाओं के जलाशयों में जल क्रीड़ा गतिविधियों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनछुए पर्यटन गंतव्यों को प्रोत्साहन प्रदान करने की दिशा में बेहतर सड़क सुविधा एक चुनौती रहती है। अनछुए पर्यटन गंतव्यों को प्रोत्साहन करने की दिशा में राज्य में सम्पर्क सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और राष्ट्रीय राजमार्गो को विस्तार प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हवाई सुविधा को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में जिला मंडी में नया एयरपोर्ट निर्मित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

उन्होंने कहा कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की आमद बहुत अधिक रहती है। प्रदेश सरकार की नई राहें नई मंजिलें और होम स्टे जैसी योजनाओं ने राज्य के अनछुए और अन्य पर्यटक स्थलों को प्रोत्साहन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक 3539 होम स्टे पंजीकृत किए गए हैं और होम स्टे संचालकों से बिजली की खपत पर घरेलू शुल्क लिया जा रहा है।

केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग और पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येस्सो नाइक, भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष संबित पात्रा, पर्यटन मंत्रालय के सचिव अरविंद सिंह, नीति आयोग के सदस्य विनोद कुमार पॉल, महानिदेशक पर्यटन मंत्रालय एवं आईटीडीसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक जी. कमला वर्द्धन राव, पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव राकेश कुमार वर्मा, राज्य पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार, निदेशक अमित कश्यप, जिला कांगड़ा के उपायुक्त निपुण जिंदल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

एसजेवीएन ने 100 मेगावाट राघनेस्दा सौर परियोजना के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किया

शिमला/शैल। नन्द लाल शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एसजेवीएन ने अवगत करवाया कि कंपनी ने मैसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ गुजरात के राघनेस्दा में 100 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना के लिए इंजीनियरिंग प्रापण और निर्माण अनुबंध हस्ताक्षरित किया है। 612.71 करोड़ रुपए के इस अनुबंध में संयंत्र का तीन वर्ष के लिए व्यापक संचालन और रखरखाव सहित एसजेवीएन को कमीशन किए गए सोलर प्लांट की आरंभ से अंत तक की आपूर्ति शामिल है। नन्द लाल शर्मा ने आगे बताया कि एसजेवीएन ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) द्वारा आयोजित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 2.64 रुपए प्रति यूनिट के टैरिफ पर इस परियोजना को हासिल किया था। इस परियोजना को वर्ष 2023 में कमीशन किया जाना है और 28.8% क्षमता उपयोग फैक्टर के साथ 252 मिलियन यूनिट का वार्षिक ऊर्जा उत्पादन करेगी। इस परियोजना से उत्पादित विद्युत को 25 वर्षो के लिए जीयूवीएनएल द्वारा खरीदा जाएगा जिसके लिए 03 जनवरी 2022 को पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एसजेवीएन के कार्यकारी निदेशक (विद्युत अनुबंध), सलिल शमशेरी और मेसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के प्रमुख (बिजनेस डवेल्पमेंट) वेपुल जैन द्वारा अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर एसजेवीएन और मेसर्स टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

वर्तमान में, नवीकरणीय परियोजनाओं के विकास पर मुख्य फोकस के साथ एसजेवीएन के पास लगभग 42,000 मेगावाट का पोर्टफोलियो है। एसजेवीएन ने हाल ही में राज्य में 10,000 मेगावाट सौर पार्क/परियोजनाओं के विकास के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, एसजेवीएन ने पंजाब राज्य में 5000 मेगावाट की सौर परियोजनाओं को विकसित करने में भी गहन रुची व्यक्त की है। इन हाल ही की उपलब्धियों के साथ, एसजेवीएन वर्ष 2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 25000 मेगावाट और वर्ष 2040 तक 50000 मेगावाट स्थापित क्षमता के अपने साझा विजन को हासिल करने की ओर अग्रसर है।

शिमला शहर के लिए अभिनव शहरी परिवहन रज्जू मार्ग परियोजना को केंद्र सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पहाड़ी क्षेत्रों में रज्जू मार्गो जैसे ईको-फ्रेंडली परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। विशेषकर, राजधानी शिमला में वाहनों की भीड़ तथा प्रदूषण कम करने के लिए 1546.40 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की अभिनव शहरी परिवहन रज्जू मार्ग परियोजना का खाका तैयार किया गया है और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 14.69 किलोमीटर लंबे इस रज्जू मार्ग नेटवर्क में 15 स्टेशन होंगे। तारादेवी मंदिर से आरंभ होने वाले इस रज्जू मार्ग में स्मार्ट पार्किंग, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और कई अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला में वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करने, प्रदूषण कम करने और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में यह अभिनव शहरी रज्जू मार्ग परियोजना एक मील पत्थर साबित होगी। यह पूरी तरह ईको-फ्रेंडली एवं कार्बन न्यूट्रल परियोजना होगी। जय राम ठाकुर ने बताया कि तीन लाख से अधिक आबादी वाले शिमला शहर में हर वर्ष लगभग 40 लाख पर्यटक आते हैं। ऐसी परिस्थितियों में रज्जू मार्ग परियोजना परिवहन का एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के वित्त पोषण के लिए प्रदेश सरकार ने न्यू डवेल्पमेंट बैंक (एनडीबी) के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है और सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डवेल्पमेंट कॉरपोरेशन (आर.टी.डी.सी.) पांच वर्ष में इस परियोजना का कार्य पूरी करेगी और यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी। शिमला में रज्जू मार्ग परियोजना का कार्य पूर्ण होने के बाद प्रदेश सरकार धर्मशाला और मनाली में भी इस वैकल्पिक परिवहन प्रणाली विकसित करेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि रज्जू मार्गो के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने रोपवे परियोजनाओं को प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की सूची में शामिल किया है। रज्जू मार्ग परियोजनाओं के लिए राईट ऑफ वे को एफसीए और (ईसी) पूर्व पर्यावरण मंजूरी में भी छूट दिलाई गई है। रज्जू मार्गो के किराये में जीएसटी की दर 18 से घटाकर 5 प्रतिशत करवाई गई है। आरआईडीएफ-नाबार्ड के तहत वित्त पोषण के लिए रज्जू मार्गो को पात्र श्रेणी में शामिल करवाया गया है। उन्होंने कहा कि जिला मंडी में पंडोह के पास माता बगलामुखी मंदिर के लिए रज्जू मार्ग योजना देश में आरआईडीएफ-नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषित पहली रज्जू मार्ग परियोजना है, जिसका कार्य अगले वर्ष 31 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है।

जय राम ठाकुर ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रदेश में रज्जू मार्गो के विकास के लिए 26 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और पर्वतमाला योजना के तहत जिला कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, सिरमौर, शिमला और बिलासपुर में लगभग 60.6 किलोमीटर के रज्जू मार्गो के लिए 2964 करोड़ रुपये की लागत वाली सात परियोजनाएं प्रस्तुत की हैं और इनके क्रियान्वयन का कार्य जारी है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या केन्द्रीय नेताओं की रैलियों से ही सत्ता में वापसी हो जायेगी?

सत्ता में वापसी के लिये 5 वर्षों में सरकार के कार्यों की रहेगी प्रमुख भूमिका

ई–चुनाव प्रचार वाहनों पर धूमल का चित्र न होने से समर्थकों में रोष

शिमला/शैल। जयराम सरकार सत्ता में वापसी करने का दावा कर रही है इस दावे को अमली शक्ल देने के लिए मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश का भ्रमण करके हर चुनाव क्षेत्र में करोड़ों की योजनाएं घोषित की है। हर जन योजना के लाभार्थियों के सम्मेलन आयोजित किये हैं। मुख्यमंत्री ने इन प्रयासों के साथ ही प्रधानमंत्री सहित कई के केंद्रीय नेता की प्रदेश में रैलियों का आयोजन प्रस्तावित है। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की रामपुर रैली से इसका आगाज भी हो गया है। 24 तारीख को प्रधानमन्त्री की मंडी में रैली घोषित है। करोड़ों रुपए इन आयोजनों पर खर्च किये जा रहे हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ऐसे आयोजनों पर होने वाला खर्च सरकारी कोष से ही होना है यह सब जानते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि इन आयोजनों से प्रदेश के आम आदमी को क्या लाभ मिलेगा? या चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य नेतृत्व हार की जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व पर डालने की पटकथा इस माध्यम से लिख रहा है। जैसा कि चारों उपचुनाव हारने के बाद यह जिम्मेदारी महंगाई पर डाल दी गयी थी। क्योंकि मुख्यमंत्री ने चुनाव क्षेत्रों में घोषणाएं उस समय की है जब वह चुनाव तक किसी भी गणित से जमीन पर क्रियात्मक रूप से नहीं उतर पायेगी। जनता इन घोषणाओं को पहले ही चुनावी जुमले मान रही है। इनका लाभ तब मिलता है यदि बजट सत्र के बाद इन पर काम शुरू हो जाता तो आज लाभार्थियों के सम्मेलनों की बजाये व्यवहारिक रूप से जनता को इन्हें दिखाया जाता। उस सूरत में केन्द्रीय नेताओं के पास भी सरकार को लेकर कुछ सकारात्मक कहने को होता। स्मृति ईरानी का स्वागत लोग काले झण्डों से न करते। केन्द्र से आने वाले हर नेता को जब अब तक मिले जुमले याद दिलाये जायेंगे तो इन आयोजनों का क्या अर्थ रह जायेगा। आज 2014 के मुकाबले रसोई गैस के दाम तीन गुना से भी ज्यादा बढ़े हुये हैं। उज्जवला योजना में 1.38 लाख को मुफ्त गैस देने का आंकड़ा परोसा जा रहा है। लेकिन क्या लोग दूसरी बार सिलैण्डर भरवा पाये हैं। राज्य सरकार की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक ही 70% दूसरी बार गैस नहीं भरवा पाये हैं। क्या लाभार्थी सम्मेलन में इन लोगों को ले जाकर स्थिति बदल जायेगी शायद नहीं। आज हिमाचल भारत सरकार की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी में पहले टॉप छः राज्यों में शामिल है। जनधन में शुन्य बैलेन्स के नाम पर खोले गये खातों में कितनों में लेन–देन हो पाया है क्या इसका आंकड़ा सरकार जारी कर पायेगी? आज हिमाचल विश्वविद्यालय में अध्यापकों की भर्ती के मामले में बड़े स्तर पर घपला हुआ है। सीपीएम ने पूरे घपले का रिकॉर्ड आरटीआई के माध्यम से सार्वजनिक कर दिया है। विपक्ष इस पर उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहा है लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं बोल पा रही है। अभी तक मनरेगा का कोई पैसा फील्ड में जारी नहीं हो सका है। गांव में इसको लेकर रोष है। लेकिन सरकार मनरेगा के जॉब कार्ड धारकों को भी लाभार्थियों की रैलियों में आने के लिये बाध्य कर रही है। इस तरह यह बड़ा सवाल बन गया है कि अब लाभार्थियों के धैर्य का बांध कहीं टूट कर सरकार के लिये घातक न सिद्ध हो जाये। सरकार ने जो पांच सालों में काम करने के दावे किये हैं लोग उनको अब अपने आसपास जमीन पर तलाश रहे हैं जहां उसे कुछ नहीं मिल रहा है। अभी पशुओं में फैलें लम्पी रोग को लेकर विभाग ने बड़े दावे किये हैं जबकि जमीनी हकीकत यह है कि सारे पशु औषधालय में डॉक्टर तैनात ही नहीं हैं। मंत्री के अपने चुनाव क्षेत्र में ही एक एक डॉक्टर के पास तीन–तीन औषधालयों की जिम्मेदारी है। इसी के साथ राजनीतिक स्तर पर भी भाजपा की एकजुटता भी कांग्रेस की ही तरह है। अभी भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिये ई–वाहनों को प्रदेश के कुछ स्थानों से हरी झंडी दिखाई है। हमीरपुर में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी शामिल थे यहां पर ई –वाहन को हरी झण्डी पूर्व मुख्यमन्त्री प्रेम कुमार धूमल ने दिखाई। लेकिन उसी वाहन पर से धूमल का चित्र गायब था। इस पर सुरेश कश्यप ने इसकी जिम्मेदारी हाईकमान पर डाल दी। हिमाचल के लिये हाईकमान केवल जे. पी.नड्डा है क्योंकि वह हिमाचल से हैं। धूमल के विश्वसतों के प्रति अभी पार्टी में वातावरण सौहार्दपूर्ण व्यवहारिक रूप से नहीं हो पाया है। जयराम सरकार के खिलाफ जितनी आक्रमकता अब तक अपनों की ओर से सामने आ चुकी है उतनी विरोधियों से नहीं है। आज जो भी केन्द्रीय नेता हिमाचल आयेगा उससे उसी स्तर के दर्जनों सवाल जवाब मांगने के लिये तैयार हैं क्योंकि यह चुनाव पार्टी की नीतियों की बजाये पांच वर्षो में इस सरकार द्वारा किये गये कामों पर ज्यादा निर्भर करेगा।

पेड कार्यकर्ताओं के सहारे कब तक चल पायेगी हिमाचल की आप ईकाई

पार्टी के भीतर चर्चित होने लगा है यह मुद्दा

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी ने चार चुनाव क्षेत्रों फतेहपुर, नगरोटा श्री पांवटा साहिब और लाहौल स्पीति से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। लेकिन जब पार्टी इन नामों को अन्तिम रूप दे रही थी उसी दौरान कुछ नेता आप छोड़कर कांग्रेस में जा रहे थे। पंजाब में जीत दर्ज करने के बाद आप ने हिमाचल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और बहुत लोग आप में शामिल भी हुये थे। लेकिन जैसे ही भाजपा के अनुराग ठाकुर ने इसमें सेन्ध लगाकर प्रदेश संयोजक सहित तीन नेताओं को भाजपा में शामिल करवा दिया उसके बाद से पार्टी में कोई बड़े चेहरे शामिल नहीं हो पाये हैं। बल्कि उसके बाद जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ उसमें बहुत सारे पुराने महत्वपूर्ण लोगों को हाशिये पर धकेल दिया गया। पूर्व डी. जी.पी. भण्डारी एक बड़ा नाम था जो अब निष्क्रिय होकर बैठ गया है। अभी तक पार्टी प्रदेश भाजपा और जयराम सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा लेकर जनता में नहीं आ पायी है। हिमाचल में पार्टी आगे बढ़ने के लिये पंजाब में आप की सरकार होने को आधार बनाकर चल रही है। अब जब पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गये हैं तब प्रदेश इकाई में ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं है जो उन सवालों का जवाब देने के लिये सामने हो बल्कि अब जब राजन सुशान्त फिर से आप में आ गये हैं तब से फिर यह आशंका हो गयी है कि प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में फिर से कोई बदलाव हो जाये। इस समय यदि किसी कारण से पंजाब की सरकार आने वाले दिनों में विवादित हो जाती हैं तो हिमाचल इकाई के पास अपना कुछ भी नहीं रह जायेगा। क्योंकि प्रदेश में जो भी नेतृत्व अब तक सक्रिय है वह व्यवहारिक रूप से दिल्ली सरकार के अच्छा शासन देने और भ्रष्टाचार पर नकेल डालने तथा भ्रष्टाचार के आरोपी अपने ही मंत्री को जेल भेजने के सूत्र वाक्यों से आगे नहीं बढ़ पाया है।

प्रदेश इकाई पर इस समय कौन निवेश कर रहा है? यह धन कहां से आ रहा है? इस समय प्रदेश में आप हाईकमान द्वारा भेजे करीब डेढ़ सौ लोगों की टीम सक्रिय है। यही टीम प्रदेश के नेताओं कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी करती है। यह टीम की व्यवहारिक रूप से सर्वेसर्वा है। इसके सामने स्थानीय कार्यकर्ता और नेता केवल मोहरे हैं। यह टीम पार्टी के अपने पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं की नहीं है। बल्कि एक तरह व्यवसायिक लोग हैं जो मोटी पगार लेकर राजनीतिक काम कर रहे हैं। अब यह चर्चा पार्टी के भीतर बड़े पैमाने पर चल पड़ी है। यहां तक कहा जा रहा है कि नयी कार्यकारिणी के गठन में भी इन्हीं लोगों का हाथ है। पार्टी के भीतरी सूत्रों के मुताबिक इस समय तक करीब दो करोड़ प्रतिमाह का निवेश प्रदेश में हो रहा है। चुनावों के दौरान यह निवेश कई गुना बढ़ेगा यह तय है। स्वभाविक है कि राजनीतिक दल के लिये पैसा तो चाहिये ही। फिर आज के राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली एकदम कारपोरेट घरानों जैसी हो गयी है। इसके लिये निवेश तो चाहिये ही। यह निवेश उद्योगपतियों के अतिरिक्त और कहीं से मिल नहीं सकता। क्योंकि पार्टी के सदस्यों के शुल्क से तो कार्यालय का बिजली–पानी का बिल भी नहीं भरा जा सकता है।

आम आदमी पार्टी के संद्धर्भ में यह चर्चा इसलिये प्रसांगिक हो जाती है क्योंकि इसका नेतृत्व भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का दावा करता है। यह भी दावा करता है कि उसकी सरकार कर्ज के सारे नहीं चल रही है। जबकि केजरीवाल सरकार पर भी पचास हजार करोड़ का कर्ज होने का खुलासा आर.बी.आई. की उस रिपोर्ट के बाद सामने आ चुका है जिसमें तेरह राज्यों की सूची जारी की गयी थी। इस सूची में पंजाब भी शामिल है। आर.बी.आई. के मुताबिक यह कर्ज लेने की सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पंजाब की वित्तीय स्थिति बिगड़ेगी। तब संसाधन बेचने और कर्ज लेने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह जायेगा। यही स्थिति हिमाचल की होने वाली है। अभी कर्ज लेने के लिये प्रतिभूतियों की नीलामी करनी पड़ी है। लेकिन इस स्थिति पर आज कोई भी विपक्षी दल सरकार से सवाल पूछने का साहस नहीं कर रहा है। आप का नेतृत्व दिल्ली और पंजाब की जो स्थिति हिमाचल में परोसकर एक राजनीतिक माहौल खड़ा करने का प्रयास कर रहा है उसके परिदृश्य में आप से यह सवाल उठाने आवश्यक हो जाते हैं। क्योंकि अब तक यही होता रहा है कि दिल्ली से आकर कोई भी नेता प्रदेश को गारंटी की घोषणा कर के चला जाता है और स्थानीय नेतृत्व उस की माला जपता रहता है। इससे यही संदेश जाता है कि हिमाचल का संचालन दिल्ली से ही होगा।

आप के चार चुनाव क्षेत्रों के उम्मीदवार

डॉ. राजन सुशान्त (फतेहपुर)

उमाकान्त डोगरा (नगरोटा)

मनीष ठाकुर(श्री पांवटा साहिब)

सुदर्शन जसपा (लाहौल स्पीति)